HIKE IN PRICE OF NEWSPRINT

3169. SHRI AJIT P. K. JOGI :

CHOWDHRY HARI SINGH :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Hindustan Newsprint Limited have hiked the prices of indigenous newsprint ;

(b) if so, the extent of price hike per tonne made by the Hindustan Newsprint Limited ;

(c) the reasons for hike in the newsprint price ; and

(d) the steps Government propose to take to bring down the prices of Newsprint in the country ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) to (c) In order to compensate partly the increase in the cost of production, the Hindustan Newsprint Ltd., increased the price of 46/49 g.s.m. newsprint by Rs. 1000 per tonne with effect from 21st June, 1993.

(d) There is no statutory control over the price of newsprint.

REVITALISATION OF P.S.Us

3170. SHRI AJIT P. K. JOGI :

CHOWDHRY HARI SINGH :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether revival of sick units and revitalisation of public sector undertakings were discussed in the International Labour Organisation Conference held in Geneva on June 12, 1992 ;

(b) what steps are being taken to revive the sick industrial units and to provide alternative jobs or means of livelihood to the affected workers ; and

(c) the number of workers and others who have been rendered jobless because of sickness during the last three years ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SHRIMATI KRISHNA SAHI) : (a) There was no reference about revival of sick units and revitalisation of PSUs in the discussion in the International Labour Organisation Conference held in Geneva on June 12, 1992.

(b) and (c) Sick industrial undertakings have been referred to BIFR for formulation of revital/rehabilitation packages. Operating agencies have been appointed by the BIFR. In order to protect the interest of affected workers National Revival Fund has been set up by the Government as a Safety net. No worker can be considered as rendered jobless because of sickness.

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को हुआ घाटा

3171. श्री अजीत जोगी :

चौधरी हरि सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड घाटे में चल रहा है, यदि हां, तो इसका यूनिटवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के लाभ तथा कारोबार का वर्षवार तुलनात्मक ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार इस कंपनी को लाभप्रद बनाने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए जाने वाले सम्भावित उपायों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिकी विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) :

(क) जी नहीं । "भेल एक लाभ कमाने वाली कंपनी है ।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान "भेल का लाभ और कारोबार इस प्रकार रहा :

(करोड़ रुपए लगभग)

	1990-91	91-92	92-93
कर पूर्व लाभ	201	187	309
कारोबार	3154	3331	3508

(ग) और (घ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

भारी उद्योग विभाग के अन्तर्गत कार्यरत सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

3172. **श्री प्रदीप जोगी**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रक के अन्तर्गत कार्यरत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार तथा स्थानवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इनमें से कुछ उपक्रम इंजीनियरी क्षेत्र में भी हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इंजीनियरी क्षेत्र में ऐसे उपक्रम स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिकी विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) :

(क) भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन चल रहे सरकारी क्षेत्र के 48 उपक्रमों की इकाइयों के राज्य/संघ, राज्यवार तथा क्षेत्रवार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण अनुबंध में दिया गया है। [देखिए परिशिष्ट 169, अनुपत्र सं. 61]

(ख) और (ग) 28 सरकारी उपक्रम इंजीनियरी क्षेत्र में हैं। ब्यौरे विवरण में दर्शाए गए हैं ।

विवरण

भारी उद्योग विभाग के अन्तर्गत इंजीनियरी प्रभाग के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सूची ।

1. एन्ड्रू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड
2. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
3. बर्न स्टण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड
4. भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस लिमिटेड
5. रेरोल बर्न लिमिटेड
6. जेसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड
7. बेथवट एण्ड कम्पनी लिमिटेड
8. भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड
9. भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियरिंस लिमिटेड
10. बेबर्ड (इण्डिया) लिमिटेड
11. लगन जूट मशीनरी कम्पनी लिमिटेड
12. भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स लिमिटेड
13. भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसरस लिमिटेड
14. रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लिमिटेड
15. त्रिवणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड
16. तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्टसलिमिटेड
17. हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
18. एच. एम. टी. लिमिटेड
19. इन्स्ट्रूमेन्टशन लिमिटेड
20. साइकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड
21. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड
22. माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड
23. नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड